(ग) गेहूं की किन-किन किस्मों का निर्यात किया जाएगा ;

(घ) गेहूं के निर्यात का देश में खाद्यान्नों की आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार क्या-क्या कदम उठाने का विचार रखती है और

(ङ) गेहूं के निर्यात से गेहूं की फसल उगाने वाले किसानों को क्या लाभ मिलेगा और इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) से (ङ) भारतीय खाद्य निगम से सुखम स्टाक स्थिति की दृष्टि में केन्द्रीय पूल से गेहूं और चावल का निर्यात करने की संभावनाओं के सम्बन्ध में एक नोट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है । तदनुसार, भारतीय खाद्य निगम ने गेहूं और चावल का निर्यात करने की संभावनाओं के संबंध में अपना जायजा लगाते हुए एक नोट प्रस्तुत किया है । सरकार ने केन्द्रीय पूल से गेहूं और चावल का निर्यात करने के संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है ।

Import/Export of sugar

7163. SHRI J. S. RAJU: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) what is the quantity of sugar exported every year, particularly in the year 1990, 1991, 1992 and 1993;

(b) what is the total amount of sugar imported from other countries to meet the growing demand of the public; and

(c) if the production is self-sufficient by when Government propose to stop export of sugar to other countries taking into consideration the piquant situation India faces?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI KALP NATH RAI): (a) As per information received from the Indian Sugar & General Industry Export Import Corporation Ltd., a designated Export Agency, the quantity of sugar exported during the financial years 1990-91, 1991-92, 1992-93 and 1993-94 was as under:—

Year	Quantity (in Metric Tonne)
1990-91 . . .	22176
1991-92 . . .	483137
1992-93 . . .	362662
1993-94 . . .	285192

(b) With a view to augment supply of sugar in the domestic market and to keep prices under check, Government has allowed import of sugar under Open General Licence. The total quantity of sugar imported/ to be imported would depend upon the contracts made by the individual firms/parties. Government has no role to play in these imports.

(c) Keeping in view the decline in production and limited availability of sugar for domestic consumption, Government has decided not to undertake any further export of sugar, excepting preferential quota to USA and EEC and a small quantity of sugar to Nepal under the Indo-Nepal Treaty a Trade.

चीनी का आयात

7164. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में चीनी की बढ़ती हुई कीमतों को नियंत्रित करने के लिए चीनी का आयात करने की घोषणा की है ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा चीनी के आयात की सुविधा की घोषणा करने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी के मूल्यों में वृद्धि हो गई है और

आयातित चीनी की कीमत भी स्वदेशी उत्पादित चीनी के मूल्य के बराबर हो जाने की संभावना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और क्या कारण है कि सरकार ने खुले बाजार में चीनी के मूल्य कम करने की दृष्टि से खुले बाजार में चीनी की मांग को कम करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मार्फत बेची जाने वाली चीनी की मात्रा में वृद्धि करने का निर्णय नहीं किया ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) चालू मौसम (1993-94) के शेष भाग के दौरान व अगले मौसम के प्रारम्भ में चीनी के मूल्यों को नियंत्रण में रखने तथा चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने खुले सामान्य लाइसेंस (ओ. जी. एल.) के तहत चीनी आयात करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है । ऐसे आयात पर कोई सीमा शुल्क या अतिरिक्त सीमा शुल्क नहीं लगाया जाएगा ।

(ख) आयातित चीनी का मूल्य लदन दैनिक मूल्य (एल. डी. पी.) पर निर्भर करता है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की मांग व पूर्ति की स्थिति के अनुसार उतार-चढ़ाव आता रहता है । 15-3-1994 को जब खुले सामान्य लाइसेंस के तहत चीनी का आयात करने की घोषणा की गई थी तब चीनी का लंदन दैनिक मूल्य 340 यू. एस. डालर प्रति मी. टन (एफ. ओ. बी.) था । इसके बाद एल. डी. पी. में उतार-चढ़ाव आता रहा है तथा 6-5-1994 को 339 यू. एस. डालर प्रति मी. टन (एफ.ओ. बी.) था ।

चूंकि खुले सामान्य लाइसेंस के तहत चीनी के आयात की अनुमति दे दी गई है इसलिए यह आयातकों पर निर्भर करता है कि वे चीनी के लिए अपने सर्वोत्तम वाणिज्यिक निर्णय के अनुसार उचित मूल्यों पर अनुबंध करें ।

(ग) 1992-93 मौसम तथा चालू 1993-94 मौसम के दौरान चीनी के उत्पादन में गिरावट के कारण लेवी चीनी सीमित मात्रा में उपलब्ध है तथा इस समय लेवी चीनी के आवंटन को बढ़ाना संभव नहीं होगा ।

Wheat Storage problems in Punjab and Haryana

7165. SHRI PRAMOD MAHAJAN: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether Punjab and Haryana are facing major wheat shortage problems as reported in the 'Times of India' of 12th April, 1994;

(b) if so, what are the details in this regard;

(c) what were the targets fixed and actual procurement of wheat in the States of Punjab and Haryana during each of the last three years;

(d) what are the targets fixed for the procurement of wheat in these States for the current year and what is the extent of procurement made so far;

(e) what timely steps were taken for creation of adequate storage facilities in these States; and what is the present storage capacity in each State; and

(f) what steps are being taken to ensure that sufficient storage facilities are made available for the storage of the wheat and rice procured by Government?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI KALP NATH RAI): (a), (b), (c) and (f) No, Sir. Food Corporation of India is having sufficient covered and CAP storage capacity in Punjab and Haryana States to meet the storage requirements. The total storage